'अप्प दीपो भव'

वॉयस ऑफ बुद्धा

Postal Reg. No.-DL(ND)-11/6144/2016-18
WPP Licence No.- U(C)-101/2017-18
R.N.I. No. 68180/98

Date of Publication : 15.11.2018
Date of Posting on concessional rate :
2-3 & 16-17 of each fortnight

मूल्य : पाँच रूपये

प्रेषक : डॉ0 उदित राज (राम राज) चेयरमैन – जस्टिस पब्लिकेशंस, टी–22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001, फोन : 23354841–42

Website : www.uditraj.com E-mail: parisangh1997@gmail.com

● वर्ष : 21 ● अंक 23 ● पाक्षिक ● द्विभाषी ● कुल पृष्ठ संख्या 8 ● 1 से 15 नवबंर, 2018

आरक्षण खत्म करने का षड्यंत्र

डॉ. उदित राज

कभी सार्वजानिक उपक्रमों की संख्या 300 से अधिक हुआ करती थी, लेकिन समयान्तराल संख्या घटती जा रही है । निजी क्षेत्र उस समय आवश्यकता पूरी करने की स्थिति में नहीं था इसलिए सरकारों ने विभिन्न तरह के सार्वजानिक उपक्रम स्थापित किए। कुछ बड़े उपक्रमों का उल्लेख करना जरुरी है, जैसे भारत संचार, नगर निगम लिमिटेड, ओएनजीसी, तेल की कम्पनियां, रक्षा उत्पाद उपक्रम, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कोयले की कम्पनियां इत्यादि। यूरोप में औद्योगीकरण की प्रक्रिया 1600 सदी से शुरू हुई और 19वीं सदी तक आते–आते चरमसीमा तक पहुंचा और इस अंतराल में भारत में नहीं के बराबर औद्योगीकरण हुआ। यूरोप और अमेरिका ने निजी क्षेत्र में न केवल तमाम क्षेत्रों में उत्पादन किया बल्कि तकनीक और खोज भी किया । 1930 के दशक में टाटा के द्वारा निजी क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाया गया जो कि इतने बड़े देश में आपूर्ति की दृष्टि से नहीं के बराबर था। अंग्रेजों ने भी कुछ उद्योग स्थापित किये लेकिन मूलरूप से ट्रेडिंग और आयात–निर्यात पर उनका जोर रहा । आज़ादी के बाद सरकारी उपक्रमों एवं विभागों का आपूर्ति एवं सेवा लगभग 80 प्रतिशत हुआ करती थी और उसकी तुलना में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 10 से 15 प्रतिशत तक ही रही।

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद दुनिया समाजवादी और पूंजीवादी खेमे में बटती है और हमारा झुकाव समाजवादी व्यवस्था के प्रति रहा। देखा जाये तो परिस्थितियां भी इसी तरह की थी क्योंकि निजी क्षेत्र बहुत पीछे रह गया था। भारत कृषि प्रधान देश रहा और इससे अपने आप बात समझ में आती है कि उद्योग धंधों के मामलों में हम सदियों से पीछे चलते रहे हैं । जातिव्यवस्था ने उत्पादन में लगे लोगों को न तो सम्मान दिया और न ही श्रम के बराबर मेहनताना । जो उत्पादन से दूर रहे और इस काम को करने में अपमान समझते थे, शिक्षा एवं सत्ता उनके पास रही अर्थात् व्यावहारिक ज्ञान महत्वहीन और काल्पनिक और केवल बौद्धिक को सर्वोपरि रखा गया, जिसकी वजह से विज्ञान, तकनीक का विकास नहीं हो पाया । उदाहरण के तौर पर लोहे के क्षेत्र में काम करने वाले को शूद्र की श्रेणी में रखा गया, और इस तरह से उसके लिए यह कार्य जीविकोपार्जन तक ही सीमित रहा न कि वह इस क्षेत्र में अनुसंधान या कोई विकास करता और धीरे–धीरे इंजीनियरिंग का एक विषय बन जाता जिसे हम मेटललोजी के नाम से जानते हैं । इसके विपरीत यूरोप में ऐसे हाथों को सम्मान से देखा गया तो उनकी रुचि न केवल जीविकोपार्जन की रही बल्कि उस क्षेत्र को लगातार कुछ नया करने का जूनून बना रहता रहा । यही कारण है कि हमारे यहाँ मशीनीकरण एवं औद्योगीकरण न हो सका। परिस्थिति भले ही क्यों न सरकार के अधीन उद्योग धंधे लगाने की रही हो लेकिन दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि निजी क्षेत्र के पास न तो पूंजी थी, न मशीनें और न ही इनको संचालित करने का अनुभव । जब हम उद्योग धंधे और व्यवसाय की बात करते हैं तो यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि सांस्कृतिक और सामाजिक परिस्थिति कैसी है ? आज भी हमारे निजी क्षेत्र शोध, तकनीक और विकास आदि में नहीं के बराबर हैं और लगभग 95 प्रतिशत मशीनें उपकरण आदि आयातित होते हैं । कुछ मामलों में ज्यों का त्यों इस्तेमाल कर लिया जाता है और उनमें परिस्थितिवश थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उपयोग किया जाता है । जिन देशों में औद्योगीकरण, मशीनीकरण, विज्ञान एवं तकनीक का विकास हुआ, वहां पर धंधा करने के लिए निजी क्षेत्र ने खुद तकनीक और ज्ञान विकसित करके पैसा कमाया जैसे फेसबुक ने यदि उद्योग खड़ा किया तो एक नई तकनीक की खोज किया और बिल गेट्स ने विंडोज साफ्टवेयर और स्टीव जॉब ने एप्पल का अविष्कार किया । अन्य देशों में निजी क्षेत्र मुनाफा ही नहीं कमाते बल्कि शोध और विकास के ऊपर भारी धन व्यय करते हैं।

हमारे यहाँ मुक्त अर्थव्यवस्था की वकालत ज्यादा ही हो रही है । इसका सबसे ज्यादा शिकार सार्वजनिक उपक्रम हैं । वर्ल्ड बैंक, आइएमएफ आई पर यूरोप और अमेरिका हमेशा दबाव बनाये रहते हैं कि आर्थिक सुधार ज्यादा से ज्यादा और जल्दी कर दिया जाये अर्थात् सार्वजनिक उपक्रमों को विनिवेश या बेच दिया जाये । अब तो मुनाफे वाले उपक्रम बिकने लगे हैं, सेंट्रल इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड गाजियाबाद के कर्मचारी आन्दोलनरत हैं कि मुनाफे वाली कंपनी को सरकार क्यों बेच रही हैं । ब्रीजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया का भी यही हश्र हो रहा है। भारत अर्थमोवर्स लिमिटेड एवं सलेम स्टील प्लांट आदि सभी को पूंजीपतियों को देने की तैयारी है । एयर इंडिया का खरीददार कोई मिल नहीं रहा है, इतने निकम्मे सार्वजनिक उपक्रम नहीं है जितना इनको बनाया गया है, शुरु से ही नौकरशाहों को इनके ऊपर बैठाया गया और यह कहना अतिश्योक्ति नहीं है कि इनके दोहन के लिए तमाम अधिकारी सिफारिश करके जाते रहे हैं, तमाम नेताओं ने भी इनका शोषण करने में कसर नहीं रखी ।

सरकार विनिवेश के जरिये मार्केट से करीब एक लाख करोड़ रुपये जुटाना चाहती है। इसके लिए उसने एक बार फिर विनिवेश कार्यक्रम में बदलाव किया है। जानकारी के अनुसार सरकार की आमदनी बढ़ाने और वित्तीय घाटे को तय लक्ष्य के भीतर रखने के लिए सरकार अगले माह से विनिवेश कार्यक्रम में तेजी लाने जा रही है। इसके तहत जल्द ही एनटीपीसी का विनिवेश किया जाएगा। इसके करीब 3 पर्सेंट शेयर बेचे जाएंगे। इसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर की दो कंपनियों जनरल इंश्योरेंस और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनियों के कुछ और शेयर मार्केट में बेचने का फैसला किया गया है। इसके अलावा सरकार हुडको और एनबीसीसी में 10 पर्सेंट हिस्सेदारी बेचेगी। विनिवेश के लिए सरकार की ओर से जल्द ही मर्चेंट बैंकर नियुक्त किया जाएगा। चालू वित्त वर्ष के आखिर में एमएमटीसी, आईटीडीसी एवं एसटीसीमें हिस्सेदारी बेची जाएगी। विनिवेश कार्यक्रम में बदलाव और तेजी लाने के लिए सरकार मजबूर है। दरअसल, विनिवेश कार्यक्रम से सरकार को अभी तक 15,247 करोड़ रुपये ही जुटा पाई है। हालांकि बजट में विनिवेश के जरिये करीब 80,000 करोड़ रुपये उगाहने का लक्ष्य रखा था। अब हालात ऐसे बन गए हैं कि सरकार के लिए जरुरी हो गया है कि वह विनिवेश के जरिये एक लाख करोड़ रुपये जुटाए। इससे सरकार को वित्तीय घाटे को जीडीपी के परिपेक्ष्य में 3.3 पर्सेंट पर रखना मुमकिन हो जाएगा।

जितना कल्याणकारी काम सार्वजनिक उपक्रमों का रहा शायद दूसरों का नहीं, दूरदराज के क्षेत्रों में इन्हें लगाया गया जहाँ कि निजी क्षेत्र मुनाफा न होने की स्थिति में जाने से कतराते रहे । जिन पिछड़े इलाकों में ये सार्वजानिक उद्योग लगे वहां के गरीबों, आदिवासियों और दलितों के जीवन में बड़ा परिवर्तन हुआ । दलितों एवं पिछड़ों को आरक्षण की वजह से सर्वाधिक नौकरियाँ लगी, दूर–दराज इलाकों में अधिकारियों एवं नेताओं के लिए ठहरने के लिए गेस्ट रूम इत्यादि की आपूर्ति आदि करते रहे, इनके उत्पादन की वजह से निजी क्षेत्र कीमत एवं गुणवत्ता पर एकाधिकार नही बना पाया अर्थात् चेक एवं बैलेंस, जहाँ मुनाफा न हो वहां निजी क्षेत्र क्यों नही जाते ? लेह और लद्दाख में बीएसएनएल (भारत संचार निगम लिमिटेड) ही क्यों सेवाएं दे और निजी क्षेत्र न जाये । वहां सेवा देने के लिए लागत अधिक होगी और मुनाफा कम या घाटा भी हो सकता है जबकि सरकारी कम्पनियाँ लाभ को लक्ष्य बनाकर नहीं जाती हैं बल्कि सुविधा और आपूर्ति की दृष्टि से। यही हाल सिविल एविएशन का है कि एयर इंडिया सभी जगह सेवा करती रही जबकि निजी एयरलाइन्स वहां जाने की ताक पर रहते हैं, जहाँ से मुनाफा कमाया जाये। एयर इंडिया की हालत इतनी खराब न होती जितना कि नेताओं और अधिकारियों ने मिल कर बर्बाद किया । जिन सेक्टरों में पैसेंजर ज्यादा थे वहां पर निजी कंपनियों को दे दिया गया और घाटे वाला मार्ग एयर इंडिया को दिया गया। इस तरह से अन्य सरकारी उपक्रमों के साथ में बर्ताव किया गया। सरकारी होटलों को उससे भी कम दाम में बेचा गया जितना बैलेंस शीट में नकदी रहा हो । हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ भी कुछ ऐसा ही किया गया।

हमारे देश की सामाजिक सोच ऐसी नहीं है कि निजी क्षेत्र की प्राथमिकता रिसर्च एंड डेवलपमेंट, गुणवत्ता, और टैक्सेज इत्यादि दूसरे देश के पूंजीपतियों जैसा दें या करें । शुरु में मोबाइल कॉल 32 रुपये और 16 रुपये हुआ करता था तब भारत संचार नगर लिमिटेड मुनाफा करने की बजाय सार्वजनिक सेवा के नियत से मोबाइल क्षेत्र में आया तब निजी क्षेत्र वालों का एकाधिकार खत्म हुआ और धड़ा–धड़ दाम नीचे गिरे । निजी क्षेत्र नहीं चाहता था कि सरकारी कंपनी को इसका लाइसेंस मिले और मिला भी तो लगभग 7 साल बाद । मुक्त अर्थव्यवस्था की अंधाधुंध नकल न की जाए बल्कि अपनी परिस्थिति के हमारी अर्थव्यवस्था का ताना–बाना होना चाहिए । सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने के बजाय ऐसे लोगों को सौंपा जाए जो उत्पादन को बढ़ायें और घाटे से बचायें । इनकी उपस्थिति से निजी क्षेत्र मनमानी नहीं कर सकेगा और रोजगार भी सुनिश्चित कर सकेगा। सार्वजानिक उपक्रमों के मुनाफे से स्वच्छ भारत जैसे तमाम कार्यक्रम सरकारों ने चलाये, सैकड़ों एनजीओ भी इनसे सहायता लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल आदि के क्षेत्रों में काम कर रही हैं, जहाँ पर सरकारी उपक्रम लगे हैं, आसपास के क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल आदि के क्षेत्र में काम करते रहते हैं, किसी भी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है रोजगार देना और सरकारी कंपनियों ने जितना रोजगार दिया है उसकी तुलना में निजी क्षेत्र का योगदान कुछ भी नहीं रहा। क्या यह दूरदर्शिता है कि घर में पड़े हुए कीमती वस्तु को बेच दिया जाये जबकि उसे बचाकर रखना चाहिए ताकि सुरक्षित रहे हम। जब ये बिक जाएंगी तब इनके बिकने के बाद और क्या बेचेंगे । दूरदर्शिता इसी में है कि इनको मजबूत किया जाये बजाये बेचने के ?

***

सावधानः बुरी खबर

20 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति/जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को बहुत कमजोर कर दिया था। 2 अप्रैल को दलितों द्वारा भारत बंद हुआ, उसके बाद सरकार द्वारा संवैधानिक संशोधन के जरिए फिर से बहाल किया गया। इसके बाद लगा था कि कोई छेड़छाड़ नही होगी लेकिन दुर्भाग्य से सुप्रीमकोर्ट ने याचिका मंजूर कर लिया है तो इसके पीछे जरुर कोई बुरी नियत है, समय की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आरक्षण के लिए फौरन सडकों पर उतरा जायें और इसीलिए 3 दिसम्बर को रामलीला मैदान, नई दिल्ली पर विशाल रैली का आयोजन किया गया है। जिसका मुख्य उद्देश्य है उच्च न्यायपालिका में दलितों, पिछड़ों एवं अल्पसंख्यकों का आरक्षण हो। आप सभी से आग्रह है कि गुटबाजी, पार्टीबाजी सभी से उठकर भारी से भारी संख्या में इकठ्ठा हों वरना भूल जाएं कि कुछ बचने वाला है।

-डॉ. उदित राज, राष्ट्रीय अध्यक्ष

डॉ. उदित राज

के नेतृत्व में अजा/जजा परिसंघ द्वारा किए गए प्रमुख कार्य

सवाल उठ रहे है कि डॉ. उदित राज बदल गये है। डॉ. उदित राज से उम्मीद नहीं की जानी चाहिए? क्या उसी से उम्मीद करनी चाहिए जो कुछ करता हो? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? उन लोगों ने ऐसी गलत फहमी फैलाई है जो पहले से जमे हुए हैं, कोई रचनात्मक कार्य नहीं किया और स्वयं को कमजोर होने का डर है। कुछ स्वार्थी जातिवाद करके जिन्दा हैं और वही हमारी बुराई करते हैं। दिमागी खुराक की खोज में नये-नये संगठन बना कर शक्ति का बंटवारा और समाज को धोखा। ये दलित और कुचले कम से कम इतना ही कर लें कि पूर्ण जानकारी के बाद ही कोई और अवधारणा बनाए।

जो कार्य अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ पिछले 18 वर्ष में किया है अगर किसी दलित संगठन एवं नेता ने किया हो तो कोई बताने का कष्ट करे। उन कार्यो को विस्तार में न लिखकर संक्षेप में उल्लेख किया जा रहा है। परिसंघ चुनौती देता है कि संवाद या लिखित रूप से हमारे द्वारा किए गए सामाजिक कार्य इतना किसी और ने किया हो? यहां कुछ कार्यों का ही उल्लेख किया जा रहा है।

1. सन 1997 में 5 आरक्षण विरोधी आदेश जारी हुए थे और उनकी वापिसी के लिए अनुसूचित जाति व जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ का गठन हुआ था। 1997, 1998, 1999 एवं 2000 में विशाल आंदोलन और रैलियां हुई और जिसकी वजह से 81वां, 82वां एवं 85वां संवैधानिक संशोधन हुआ और आरक्षण बच पाया।

2. 4 नवम्बर 2001 को सरकारी दिक्कतों के बावजूद लाखों लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई । रामराज से उदित राज हो गए, जो ये प्रमाणित करता है कि यह जाति तोड़ने व वास्तविक सांस्कृतिक परिवर्तन का प्रयास था।

3. जब सरकारी नौकरियां खत्म हो रहीं थीं तो निजी क्षेत्र में आरक्षण का मुद्दा हमने उठाया। जब मुद्दे में जान आने लगी, तभी समाज के कुछ नेता घबरा गये और हमारा विरोध करके हमे कमजोर करने लगे। शुरुआत में आंदोलन के दबाव के कारण मनमोहन सिंह जी की सरकार ने निजी क्षेत्र में आरक्षण देने के लिए शरद पवार के नेतृत्व में मंत्री समूह की कमेटी का गठन किया। अगर समाज पूरा साथ देता तो बहुत संभव है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण अब तक मिल गया होता।

4. 2006 में जब पिछड़े वर्ग को उच्च शिक्षण संस्थानो में आरक्षण मिला तो उसका विरोध तथाकथित जातिवादी लोग करने लगे। तो परिसंघ ने ही मोर्चा संभाला और अंत में पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिला।

5. अमेरिका से लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार आयोग में दलितों के उत्पीड़न की आवाज कई बार हमने उठायी।

6. 2006 में नागराज के मामले में सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करके प्रमोशन में आरक्षण बचाने का कार्य किया । क्या देश का कोई और संगठन या व्यक्ति है जो उस समय सक्रिय हुआ? अगर डॉ. उदित राज न होते तो शायद प्रमोशन में आरक्षण उसी समय खत्म हो जाता। 85वाँ संवैधानिक संशोधन की वजह से यह विवाद खड़ा हुआ था। संशोधन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में इस अधिकार को बचाने का कार्य परिसंघ ने ही किया। जो अधिकार डॉ. उदित राज ने दिलाया वह मायावती की सरकार में छिन गया। 4 जनवरी 2011 को प्रमोशन में लखनऊ हाई कोर्ट ने आरक्षण समाप्त कर दिया । हाई कोर्ट के आदेश ने इतना गुंजाइश छोड़ी की यदि राज्य सरकार चाहे तो कुछ शर्तें पूरा करके प्रमोशन में आरक्षण आगे चालू रख सकती है । जैसे राजस्थान की सरकार ने एक समिति बनाकर प्रमोशन में आरक्षण दिया वैसा मायावती सरकार ने क्यों नही किया? सवर्ण वोट की लालच की खातिर मायावती जी स्वयं निर्णय न करके मामले को सुप्रीम कोर्ट भेज दिया और वहां पर हाई कोर्ट के फैसले पर मोहर लग गई। हमने अपनी तरफ से बहुत प्रयास किया कि मुकदमा सुप्रीम कोर्ट न जाएं लेकिन बसपा की सरकार ने एक नही सुनी? क्योंकि परिसंघ ने इस मांग को उठाया था। जरा सोचिए प्रमोशन में आरक्षण की समस्या किसने खड़ी की है? अब सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण का रास्ता साफ कर दिया है लेकिन आए दिन इसमें क्रीमीलेयर की बाद की जाती है। यदि ऐसा हुआ तो परिसंघ इसका विरोध करेगा।

7. सन 2011 में अन्ना हजारे ने जब लोक पाल बनाने का आंदोलन छेड़ा तो सारा देश दबाव में आ गया था और अकेला परिसंघ ही था कि उसने चुनौती दी कि क्या लोकपाल में दलित-पिछड़े और अल्पसंख्यक भी स्थान पाएगें? उस समय की मांग के अनुसार संसद की कार्यवाही, सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री और सीबीआई तक सभी लोकपाल के अन्दर आने की बात थी। हमने लोकपाल बिल में आरक्षण की बात उठाई तो अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल ने इसे बनवाने में रुचि ही समाप्त कर दी। मान लिया जाए कि परिसंघ द्वारा अगर अवाज नहीं उठाई गई होती तो लोकपाल बन गया होता। तो संविधान के ऊपर लोकपाल बैठ जाता और इस देश में महिलाओं, दलितों एवं पिछड़ो की हालत खराब हो जाती। हमने बहुजन लोकपाल बिल बनाकर आरक्षण की मांग की और यह मांग पूरी भी हुई।

8. 2 अप्रैल भारत बंद में लोगों पर गलत तरीके से मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल भेजा गया जिसके लिए परिसंघ ने जिले के दंडाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक से बात करके हजारों लोगों को जेल से रिहा करवाया।

9. अब तक हमने हजारों कर्मचारियों की नौकरियों को बचाया है व लाखों के तमाम भेदभाव को खत्म करने की पुरजोर कोशिश की, यही कारण है, जब परिसंघ आवाहन करता है तो लाखों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। परिसंघ किसी को भी चुनौती देता है की लिखित में कोई बहस कर ले यदि देश में किसी और नेता ने इतना कार्य किया हो तो आलोचना करो, लेकिन गलती तो बताओ ।

ज्यादातर निकम्मे ही आलोचना करते हैं। वे अपने गिरेबान में झाँककर देखें कि उन्होंने क्या किया है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोई और अम्बेडकर क्यों नही पैदा हो रहा है, तो कोई कैसे पैदा होगा जब अपने ही लोग टांग खीचते हैं? बाबा साहब की तुलना तो किसी से नहीं की जा सकती लेकिन अगर निष्पक्षता पूर्वक समीक्षा की जाए तो परिसंघ ने उस दिशा में कुछ प्रयास किया है और जारी रहेगा। 10 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य लिया गया है।

डॉ. उदित राज ने जितना दलितों के बारे में संसद में प्रश्न किए हैं, शायद किसी और ने नहीं। कर्मचारी-आधिकारी रिटायर हो रहे है उनके एवज में भी भर्ती नहीं हो पा रही है। बढ़ी हुई जनसंख्या के मुताबिक भर्ती की तो बात बहुत दूर की है। ठेकेदारी प्रथा से आरक्षण लगभग खत्म हो गया है। निजी क्षेत्र में आरक्षण की लड़ाई कमजोर होती जा रही है। पदोन्नोंति में आरक्षण की परेशानी बढ़ती जा रही है। चारो ओर अंधकार ही अंधकार है। उजाले की ओर बढ़ने के लिए अब एक होकर कुछ तो करो।

जो अम्बेडकरवादी हैं, वे सामान्यतया भगवान बुद्ध को ही मानते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा था कि जो कसौटी पर न खरी उतरे, उसे मत मानना। उन्होंने यहां तक कहा था कि उनकी भी बात जब तक कसौटी पर खरी न उतरे न मानी जाए। ये उन साथियों के लिए हैं, जो अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के साथियों के बलिदान को बिना जाने आलोचना करते रहते हैं। इस समय डॉ. उदित राज की बड़ी आलोचना इस बात को लेकर हो रही है कि वे भाजपा मे चले गए हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी में जाकर चापलूसी कर रहे हैं? या स्वयं के स्वार्थ की सिद्धि कर रहे हैं? बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर पूरे जीवन कांग्रेस को कोसते रहे। भारत-पाक बंटवारे के उपरांत जब उनकी संविधान सभा की सदस्यता समाप्त हुई तो कांग्रेस ने अपने महाराष्ट्र के मंत्री पीपुल जैकर का इस्तीफा दिलवाकर वहां से बाबा साहेब को चुनवाकर संविधान सभा में भेजा। उसके बाद बाबा साहेब को न केवल कानून मंत्री बनने का अवसर मिला बल्कि संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष भी बने। कांग्रेस में जाकर उन्होंने समाज के लिए किया तो डॉ0 उदित राज भारतीय जनता पार्टी में जाकर समाज की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, कैसे गलत हैं? उनके द्वारा संसद में उठाए गए मुद्दे एवं कार्यों को देखने के बाद अगर व्यक्ति बेईमान और पूर्वाग्रहित नहीं है तो निश्चित तौर से सराहना किए बिना नहीं रह पाएगा।

***

1998 में आरक्षण विरोधी आदेशों की वापिसी हेतु फ़िरोज शाह कोटला मैदान में विशाल रैली आयोजित की गयी

डॉ. उदित राज के नेतृत्व में लोक पाल में आरक्षण हेतु इंडिया गेट पर 24 अगस्त, 2011 को विशाल रैली की गई

निजी क्षेत्र में आरक्षण व आरक्षण कानून बनाने के लिए नवंबर-दिसंबर 2009 में डॉ. उदित राज ने आमरण अनुशन किया

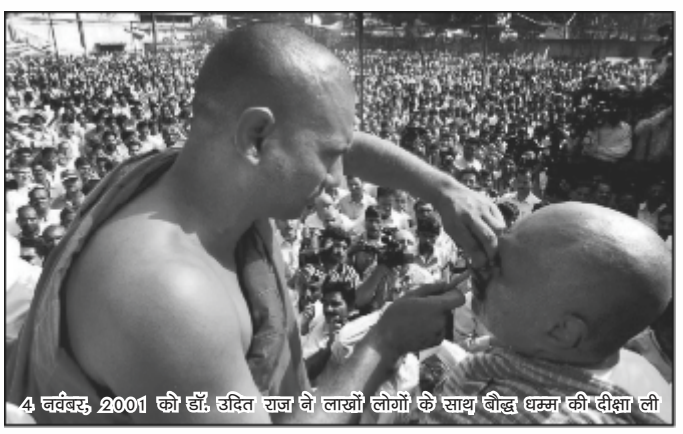
4 नवंबर, 2001 को डॉ. उदित राज ने लाखों लोगों के साथ बौद्ध धम्म की दीक्षा ली

परिसंघ का महाराष्ट्र कार्यकर्त्ता सम्मेलन संपन्न

3 नवंबर, 2018 को मुम्बई दादर स्थित शारदा मंगल कार्यालय में अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के महाराष्ट्र कार्यकर्त्ता सम्मेलन में मा. डॉ. उदित राज, राष्ट्रीय अध्यक्ष परिसंघ, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। कार्यक्रम में विषेश रूप में सुप्रसिद्ध गायका मा. सलमा आगा उपस्थित थीं । डॉ. उदित राज जी ने उपस्थित जन समूह का मार्गदर्शन किया और विभिन्न उदाहरणों से संगठन के महत्व पर बल दिया। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि मजबूत संगठन सभी समस्याओं का हल हैं। 85 प्रतिशत बहुजन समाज में सभी के अपने-अपने संगठन हैं। इन्हीं संगठनों को जोड़ने की आज जरूरत है। डॉ. उदित राज जी ने कहा कि परिसंघ कोई राजनैतिक संगठन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से सांसद बनने के बाद पार्टी लेवल से ऊपर उठकर बहुजन समाज की आवाज सभी तमाम सांसदों से ज्यादा संसद में उठाई । तो क्या यह गलत किया? चापलूसी करता तो आज मैं भी मंत्री होता। पर समाज के हितों के विराध मे मैंने कभी समझौता नहीं किया। मैं अंतिम सांस तक समाज के हितों को सर्वोपरी मानते हुए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं एवं रहूंगा। बहुजनों को अपना सोचने का नजरिया बदलना होगा। तभी समाज व राष्ट्र की प्रगति होगी। सम्मेलन में सम्पूर्ण महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में परिसंघ के कार्यकर्ता मौजूद थे। डॉ. संजय कांम्बले व संजय अढांगले व उनके सहयोगियों ने कार्यक्रम को सफल बनाने में कड़ी मेहनत की। नागपुर व विदर्भ से दीपक तभाने, एम.के. कोडापे, एम. एन.चोखांद्रे, भोजराज माहूरे, उमेश पंधरे, माणिक तैडसाम, उध्दव मुले इत्यादि बडी संख्या में उपस्थित थे।

– दीपक तभाने,
अध्यक्ष परिसंघ,
नागपुर

मुंबई में कार्यकर्त्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. उदित राज जी

सम्मेलन में मंच पर उपस्थित डॉ. उदित राज एवं संजय कांबले व उपस्थित जनसमूह

आदिवासी जननायक बिरसा मुंडा

(जन्म दिवस 15 नवंबर)

बिरसा मुंडा भारतीय क्रांतिकारी थे। वे एक धर्म गुरु और जनसाधारण लोगो के वीर नायक थे। 19 वीं सदी के आखिरी वर्षो में मुंडाओं ने महान आन्दोलन उलगुलान को अंजाम दिया जिसकी वजह से वे भारत की आजादी के इतिहास में विशेष व्यक्ति बन गये। उन्होंने अपनी आयु के 25 वर्ष के पहले ही बहुत सी विशिष्ट सफलता प्राप्त कर ली थी।

आरंभिक जीवन और बचपन : बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवम्बर 1875 को झारखंड प्रदेश में राँची के उलीहातू गाँव में हुआ था और उनका नाम मुंडा प्रथा से रखा गया था। बिरसा पहले कुछ वर्ष अपने माता पिता के साथ चल्कड़ में रहते थे। बिरसा का बचपन अन्य मुंडा बच्चो की तरह ही था। वे अपने बचपन में अपने मित्रो के साथ मिटटी में खेल कूद करना पसंद करते थे। वे बचपन में बोहोंदो के जंगलो में बकरिया भी चराते थे। जब बिरसा बड़े हो रहे थे तभी उन्हें बासुंरी बजाना पसंद था और वे तुइल भी बजाते थे। उन्होंने जिन्दगी के कुछ यादगार पल अखाड़ा में बीताए थे। पढाई में होशियार होने की वजह से "जयपाल नाग" ने उन्हें जर्मन मिशन स्कूल में प्रवेश लेने के लिए कहा। परंतु उस स्कूल में प्रवेश लेने के लिए इंसाई धर्म का होना जरुरी था। इसलिए बिरसा ने इसाई धर्म स्वीकारा और वे बिरसा मुंडा से बिरसा डेविड बन गए और फिर बिरसा दाऊद बने। कुछ वर्ष पढने के बाद बिरसा ने जर्मन मिशन स्कूल छोड़ दिया और प्रसिद्ध वैष्णव भक्त आनंद पांडे के संपर्क में आ गए और उन्होंने महाभारत, रामायण और अन्य कई हिन्दू धर्म के ग्रंथ पढ़े है।

गतिविधियाः बिरसा मुंडा ने सन 1900 में अंग्रेजो के विरुद्ध विद्रोह करने की घोषणा करते हुए कहा हम ब्रिटिश शाशन तन्त्र के विरुद्ध विद्रोह की घोषणा करते है और कभी अंग्रेज नियमों का पालन नही करेंगे, ओ गोरी चमड़ी वाले अंग्रेजो, तुम्हारा हमारे देश में क्या काम ? छोटा नागपुर सदियों से हमारा है और तुम इसे हमसे छीन नही सकते। इसलिए बेहतर है कि वापस अपने देश लौट जाओ वरना लाशो के ढेर लगा दिए जायेंगे। इस घोषणा को एक घोषणा पत्र में अंग्रेजो के पास भेजा गया तो अंग्रेजो ने अपनी सेना बिरसा को पकड़ने के लिए रवाना कर दी। अंग्रेज सरकार ने बिरसा की गिरफ्तारी पर 500 रूपये का इनाम रखा था। अब बिरसा भी तीर कमान और भालों के साथ युद्ध की तैयारियों में लग गये। बिरसा के इसके विद्रोह में लोगों को इकट्ठा किया और उनके नेतृत्व में आदिवासियों का विशाल विद्रोह हुआ था। अंग्रेज सरकार ने विद्रोह का दमन करने के लिए 3 फरवरी 1900 को मुंडा को गिरफ्तार कर लिया जब वे अपनी आदिवासी गुरिल्ला सेना के साथ जंगल में सो रहे थे। उस समय 460 आदिवासियों को भी उनके साथ गिरफ्तार किया गया। 9 जून 1900 को रांची जेल में उनकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गयी और अंग्रेज सरकार ने मौत का कारण हैजा बताया था।

जेल और मृत्यु : 3 फरवरी 1900 को मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया जब वो अपनी आदिवासी गुरिल्ला सेना के साथ जंगल में सो रहे थे। उस समय 460 आदिवासियों को भी उनके साथ गिरफ्तार किया गया था। 9 जून 1900 को रांची जेल में उनकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गयी।

लोकप्रिय संस्कृति : 15 नवंबर को बिरसा मुंडाजी की जयंती मनाई जाती है खास तौर पर तो कर्नाटक के कोडागु जिल्हे में मनाई जाती है। कोकार रांची में जो झारखंड की राजधानी है यहां पर उनकी समाधी स्थल पर बहुत से कार्यक्रम मनाए जाते हैं। उनकी स्मृति में रांची में बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारागार तथा बिरसा मुंडा हवाई-अड्डा भी है। उनके नाम से कई संस्था, कई यूनिवर्सिटी और कई इंस्टीट्यूशन भी बने हैं। 2008 में बिरसा के जीवन पर आधारित एक हिंदी फिल्म ''गाँधी से पहले गंधिवास'' बनी जो इकबाल दुरग्न के निर्देशन में बनी जिसने नोवेल पुरस्कार भी जीता है। फिर एक और हिंदी फिल्म 2004 में ''उलगुलान एक क्रांति'' बनी जिसमें 500 बिर्सेट्स भी शामिल है। ''महास्वेता देवी'' की एक लेखिका थी उन्होंने रोमन मग्सय्सय पुरस्कार जीता था। 1979 में अरण्येर अधिकार के लिए उन्होंने साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला यह पुरस्कार उन्हें मुंडाजी जे जीवन के बारे में बताया जिसमे उन्होंने 19वी सदी में ब्रिटिश राज के बारे में भी बताया था। इसके बाद उन्होंने युवाओं के लिए मुंडाजी पर आधारित एक और साहित्य लिखा था।

https://www.gyanipandit.com/birsa-munda-history-in-hindi/

***

आगामी रैली से संबंधित हैंडबिल का नमूना छापा जा रहा है। परिसंघ के नेताओं से अपील है कि प्रदेश व जिला इकाइयों की ओर से भी छपवाकर वितरित करें।

दिल्ली चलो! दिल्ली चलो!! दिल्ली चलो!!!

"अब न सहेगें अत्याचार – लेकर रहेगें सब अधिकार"

अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ

के तत्वावधान में

SC/ST/OBC का आरक्षण बचाने, उच्च न्यायपालिका एवं निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू कराने और अत्याचार पर रोक के लिए

डॉ. उदित राज
राष्ट्रीय अध्यक्ष, परिसंघ

रैली

3 दिसंबर, 2018
(सोमवार) सुबह 10 बजे

रामलीला मैदान, नई दिल्ली

भारी संख्या में भाग लेकर रैली को सफल बनाएं

AlParisangh AlParisangh 9899766443

parisangh1997@gmail.com All India Parisangh www.aiparisangh.com

पताचार : टी-22 अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 फोन : 011-23354841/42, मो. 9868978306, टेलीफैक्स : 011-23354843

प्रमुख उपलब्धियां

1. तीन संवैधानिक संशोधन कराकर आरक्षण बचाया
2. लोकपाल में आरक्षण कराया
3. 4 नवंबर 2001 को लाखों लोग बौद्ध बने
4. पदोन्नति में आरक्षण बहाल कराया
5. संसद में सबसे अधिक दलित मुद्दे उठाए
6. पिछड़ों को उच्च शिक्षा में आरक्षण का समर्थन
7. 2 अप्रैल भारत बंद में लोगों पर गलत तरीके से मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल भेजा गया जिसके लिए परिसंघ ने जिले के दंडाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक से बात करके हजारों लोगों को जेल से रिहा करवाया।
8. भीम आर्मी के चीफ चन्द्र शेखर की रिहाई में सबसे बड़ा योगदान

प्रमुख मुद्दे

1. दलितों, पिछड़ों एवं अल्पसंख्यकों का आरक्षण सुरक्षित हो
2. निजी क्षेत्र एवं उच्च न्यायपालिका में आरक्षण लागू हो
2. आरक्षण कानून बनाओ
4. सफाई के काम में ठेकेदारी प्रथा समाप्त हो
5. बैकलॉग पदों को भरने हेतु विशेष भर्ती अभियान
6. देश में समान शिक्षा नीति लागू हो एवं भूमिहीनों को भूमि
7. अनुसूचित जाति योजना एवं जन जाति उप योजना कानून बनाओ
8. एक राज्य का जाति प्रमाण-पत्र सभी राज्यों में मान्य हो
9. महंगाई की दर से छात्रवृति में बढ़ोत्तरी
10. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन और उसमें आरक्षण
11. महिला सशक्तिकरण
12. रेहड़ी-पटरी वालों को स्थाई जगह एवं लाइसेंस दिया जाए।

साथियो,

अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ दलित नेतृत्व बचाने की चिंता से ज्यादा अधिकार बचाने के लिए लड़ता रहा है। मात्र यही संगठन है जो 1997 से मूल रूप से आरक्षण बचाने की लड़ाई लड़ता आ रहा है। ज्यादातर अन्य संगठन अपनी जाति के नेता को बचाना ही मिशन समझते हैं और जमीनी लड़ाई लड़ने के बजाय बंद कमरों और हॉल में मिशन की बात करते रहते हैं। 20 वर्ष से अधिक समय से परिसंघ अधिकार बचाने की प्राथमिकता के साथ अकेले पूरी सत्ता को झुका न सका क्योंकि दूसरे साथ नहीं दिए। भले ही हमारी बात को कुछ लोग आज भी न समझें लेकिन आने वाले दिनों में जरुर याद करेंगे। कितनी बड़ी त्रासदी है कि बहुजन समाज में जितनी तेजी से जागृति हुई और उसी अनुपात में सरकारी नौकरियां और शिक्षा की भागीदारी घटी। लोग भावुक होकर अधिकार बचाने से ज्यादा नेता बचाने में लगे रह गए। सरकारी नौकरियां लगभग खत्म हो चुकी हैं और शिक्षा का भी निजीकरण हो चुका है। हजारों इंजीनियरिंग कॉलेज, सैकड़ों मेडिकल कॉलेज एवं विश्विद्यालय भी निजी क्षेत्र में खड़े हो गए हैं और ऐसे में अच्छी और महँगी शिक्षा से बहुजन समाज वंचित हो गया।

सन 1993 में उच्च न्यापालिका में जजों की नियुक्ति में राजनैतिक नियुक्ति की भागीदारी खत्म की जाती है, उस समय अगर बहुजन नेता सड़क से संसद तक संघर्ष करते तो संसद से मिले अधिकार न तो न्यापालिका छीन पाती और न ही दलितों व अल्पसंख्यकों को जेल भेजने का आरक्षण विरोधी फैसले देती। ऐसा आखिर में होता ही क्यों ? समाज के चंद लोग निजी फायदे के लिए विधायक, सांसद और सत्ता की लालच में लगे थे और आम जनता भावना में अपनी-अपनी जाति के नेता को ही मजबूत करने में लगी रही। 3 दिसम्बर, 2018 (सोमवार) को रामलीला मैदान, नई दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट घेरने के लिए अगर लाखों लोग मार्च नहीं करते, तो भले ही संसद और विधानसभा से कानून बनवा लें लेकिन न्यायपालिका रुकावट डालती ही रहेगी। दूसरे देशों में जब जज पक्षपाती हुए तो लोगों ने आन्दोलन किया और अमेरिका में अश्वेतों ने हर स्तर पर इतना विरोध किया कि गोरे जज डरने लगे और न्याय करने में भेदभाव करना बंद कर दिया। जब तक न्यायपालिका में दलितों और पिछड़ों का आरक्षण नहीं होता, तब तक न्याय की आशा करना नादानी होगी। जज सबकी योग्यता की जाँच करते हैं, जो स्वयं भाई-भतीजे और जाति के आधार पर नियुक्त होते रहते हैं। जब किसी वकील का नाम जज के लिए अग्रसारित किया जाता है तो क्या उनकी कोई लिखित परीक्षा होती है या साक्षात्कार अथवा उनके द्वारा निबटाए गए मुकदमों की फाइलों की जाँच पड़ताल को आधार बनाया जाता है ? जो मेरिट के आधार पर खुद ही न नियुक्त हुआ हो, वह दूसरों की मेरिट कैसे तय कर सकता है ? जिस तरह से सिविल सेवा में भर्ती होती उसी तरीके से आल इंडिया ज्युडिशियल सर्विस को तुरंत लागू किया जाए और न्यायपालिका में आरक्षण हो।

सत्ता की चाबी लेने के लिए संघर्ष जरुर हो लेकिन यह भी न किया जाए कि सत्ता के इंतजार में हम सबकुछ खो दें। जाति व्यवस्था में जब तक निजी स्वार्थ न हो तब तक अपने से नीचे वाली जाति का नेतृत्व मानने वाला कोई नहीं है। दलित और आदिवासी नीचे के पायदान पर हैं, इसलिए इनके ऊपर वाले तीनों वर्ग स्वाभाविक रूप से इन्हें नेता नहीं मानेंगे। यदि पिछड़ों में फुले, शाहू एवं पेरियार के विचारों को पैदा किया जाए तो बहुजन समाज एक हो सकता है और तब ही सत्ता की कुंजी संभव है। जाति व्यवस्था को इन दोनों को स्वाभाविक रूप से सवर्ण और वैश्य स्वीकार नहीं करेंगे। सवर्ण ही एक ऐसा वर्ग है जिसको नीचे के तीनो वर्ग अपना नेता आसानी से मानतें हैं और इसीलिए सत्ता उन्हीं के हाथ में है। सत्ता की लड़ाई चालू रहे और दूसरी तरफ जन-आन्दोलन तेज किया जाना चाहिए। 2 अप्रैल, 2018 को अगर भारत बंद न हुआ होता तो मुमकिन है कि अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण कानून न बहाल हुआ होता और न ही 5 मार्च, 2018 को यूजीसी द्वारा जारी विश्विद्यालय में शिक्षक भर्ती में कुठाराघात को रोका जा सकता था। खासतौर पर दलित आदिवासी को भूल जाना चाहिए कि उनके विधायक सांसद और मंत्री कुछ कर सकते हैं ? मूल कारण यह है कि समाज पार्टियों को वोट देता है, न कि संघर्ष करने वालों को और चुनाव हो जाने पर दलित नेता याद आते हैं। चाहे जितना ही संघर्ष करने वाला दलित, आदिवासी नेता होगा अगर निर्दलीय चुनाव लड़े तो उनको कोई भी वोट नहीं देता। जाट भाई ने आन्दोलन किया उनको आरक्षण मिला, पटेलों ने भी इसी रास्ते से अपनी बात मनवाई और किसान जब मुंबई की सड़कों पर लाखों की संख्या में उतरे तो कर्ज माफ हुआ।

डॉ. उदित राज, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ, ने जितनी आवाज संसद में उठाई क्या किसी ने किया ? निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए निजी बिल संसद में पेश किया। 2 अप्रैल, 2018 को भारत बंद का खुलकर समर्थन ही नहीं किया बल्कि अगर आवश्यकता पड़ी तो पार्टी को भी नहीं बक्शा। भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर की रिहाई के लिए संसद में जोरदार आवाज उठाई। जिस तरह से 2 अप्रैल, 2018 को भारत बंद हुआ उसी तरह से लाखों लोग 3 दिसम्बर, 2018 को रामलीला मैदान, नई दिल्ली में पहुँचकर ताकत का प्रदर्शन करें। मात्र यही एक रास्ता रह गया है। यह डॉ. उदित राज एवं परिसंघ की ही नहीं, बल्कि समस्त दलित, आदिवासी, पिछड़े एवं अल्पसंख्यकों की भी लड़ाई है।

निवेदक : देवी सिंह राणा, ओम प्रकाश सिंघमार, परमेन्द्र, गिरीश चन्द्रा पाथरे, सत्या नारायण, सविता कादियान पंवार, संजय राज, राजन हिजम, आदित्य कुमार नवीन (दिल्ली), सुशील कमल, नीरज चक, राज कुमार (उ.प्र.), सिद्धार्थ भोजने, दीपक तभाने, संजय कांबले, (महाराष्ट्र), एस.पी. जरावता, विश्वनाथ, सत्यावान भाटिया, महासिंह भूरानिया (हरियाणा), तरसेम सिंह घारू (पंजाब), मनीराम बडगुर्जर, विश्राम मीना, मुकेश मीना (राजस्थान), बाबू सिंह, विजय राज अहिरवार (उत्तराखंड), आलेख मलिक, डी.के. बेहेरा (उड़ीसा), परमहंस प्रसाद, नरेन्द्र चौधरी, विपिन टोपो (म.प्र.), रामूभाई वाघेला, उत्पल कुलकर्णी (गुजरात), एस. करुपइया, पी. एन. पेरुमल (तमिलनाडु), रमन बाला कृष्णन (केरल), मधु चन्द्रा (मणिपुर), के. महेश्वर राज, प्रकाश राठौर (तेलंगाना), पालटेटी पेन्ठा राव (आंध्र प्रदेश), हर्ष मेश्राम, प्रदीप सुखदेवे (छ. ग.), पी. बाला, सदन नसकर, सुब्रता बातूल (प.बंगाल), मधुसूदन कुमार, विल्फ्रिड केरकेट्टा (झारखंड), आर.के कलसोत्रा, बी.एल. भारद्वाज (जम्मू व कश्मीर), मदनराम, शिवधर पासवान, शिव पूजन (बिहार), जे. श्रीनिवासलू, आर. राजा सेगरन, थिपेस, पी. शंकर दास (कर्नाटक), सीताराम बंसल, (हि.प्र.), प्रदीप बास्फोर, जय करण (असम), सी.बी. सुब्बा (सिक्किम), प्रकाश चन्द्र बिश्वास (त्रिपुरा)

आगामी रैली से संबधित पोस्टर का नमूना छापा जा रहा है। परिसंघ के नेताओं से अपील है कि प्रदेश एवं जिला इकाइयों की ओर से भी छपवाकर वितरित करें।

दिल्ली चलो! दिल्ली चलो!! दिल्ली चलो!!!

All India Confederation of SC/ST Organizations

"अब न सहेगें अत्याचार – लेकर रहेगें सब अधिकार"

अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय

परिसंघ

के तत्वावधान में

SC/ST/OBC का आरक्षण बचाने, उच्च न्यायपालिका एवं निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू कराने और अत्याचार पर रोक के लिए

डॉ. उदित राज
राष्ट्रीय अध्यक्ष, परिसंघ

रैली

3 दिसंबर, 2018
सोमवार, सुबह 10 बजे

रामलीला मैदान, नई दिल्ली

भारी संख्या में भाग लेकर रैली को सफल बनाएं

AIParisangh AIParisangh 9899766443 All India Parisangh www.aiparisangh.com

निवेदक : देवी सिंह राणा, ओम प्रकाश सिंघमार, परमेन्द्र, गिरीश चन्द्रा पाथरे, सत्या नारायण, सविता कादियान पंवार, संजय राज, राजन हिजम, आदित्य कुमार नवीन (दिल्ली), सुशील कमल, नीरज चक, राज कुमार (उ.प्र.), सिद्धार्थ भोजने, दीपक तभाने, संजय कांबले (महाराष्ट्र), एस.पी. जरावता, विश्वनाथ, सत्यावान भाटिया, महासिंह भूरानिया (हरियाणा), तरसेम सिंह धारु (पंजाब), मनीराम बडगुर्जर, विश्राम मीना, मुकेश मीना (राजस्थान), बाबू सिंह, विजय राज अहिरवार (उत्तराखंड), आलेख मलिक, डी.के. बेहेरा (उड़ीसा), परमहंस प्रसाद, नरेन्द्र चौधरी, विपिन टोपो (म.प्र.), रामूभाई वाघेला, उत्पल कुलकर्णी (गुजरात), एस. करुपइया, पी. एन. पेरुमल (तमिलनाडु), रमन बाला कृष्णन (केरल), मधु चन्द्रा (मणिपुर), के. महेश्वर राज, प्रकाश राठौर (तेलंगाना), पालटेटी पेन्ना राव (आंध्र प्रदेश), हर्ष मेश्राम, प्रदीप सुखदेवे (छ.ग.), पी. बाला, सदन नसकर, सुब्रता बातूल (प.बंगाल), मधुसूदन कुमार, विल्फ्रिड केरकेट्टा (झारखंड), आर.के कलसोत्रा, बी.एल. भारद्वाज (जम्मू व कश्मीर), मदनराम, शिवधर पासवान, शिव पूजन (बिहार), जे. श्रीनिवासलू, आर. राजा सेगरन, थिपेस, पी. शंकर दास (कर्नाटक), सीताराम बंसल (हि.प्र.), प्रदीप बास्फोर, जय करण (असम), सी.बी. सुब्बा (सिक्किम), प्रकाश चन्द्र बिश्वास (त्रिपुरा)

पत्राचार : टी-22 अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 फोन : 011-23354841/42, मो. 9868978306, टेलीफैक्स : 011-23354843

Dr. Udit Raj: Man from the Bottom Became a Crusader (My Memoirs of Dr. Dr. Udit Raj)

Dr. Udit Raj's life is a story of socio-economic transformation brought by the education through reservation and the power of the English and then become a crusader. First he bridged the social gap between him and his wife, who come from a higher caste family. Tapasya Productions, a film production house has created a documentary film on life of Dr. Dr. Udit Raj, Member of Parliament, Lok Sabha, North West first, who is also the National Chairman of All India Confederation of SC/ST Organizations. Mr. Luo Zhaohui of Ambassador of People's Republic of China to India said about him, "A man from the bottom of the society, who became a crusader for India's downtrodden people." Truly, Dr. Udit Raj became a crusader nationally and internationally, specifically to protect and ensure the reservation facilities to the members of Scheduled Caste and Scheduled Tribes provided by the Indian Constitution.

My memoirs begun when I heard his name for the first time, while he was leading one of the largest Dalit mass movement after Independent India on 4 November 2001. Hundreds of thousands of Dalits from all over India were coming to the national capital, where Dr. Udit Raj along with thousands decided to adopt Buddhism. The permission given conduct event at the Ram Lila ground in Delhi was cancelled at last hour by the then central government. Then the program shifted to Ambedkar Bhavan in Delhi, where Dr. Udit Raj adopted Buddhism along with thousands of India's oppressed people and also changed his name from Ram Raj. Thereafter, I met him for the first time in Chandigarh on 14 April 2003, where he celebrated Dr. B R Ambedkar's Birthday, in which hundreds of Valmiki community leaders performed Buffalo Worship and adopted Buddhism. The news of the Buffalo worship instead of worshiping cow was a huge challenge for high caste communities.

The story of Dr. Udit Raj, a man from the bottom of the downtrodden society, who later becomes a crusader is a living legend of what the reservation and the power of English can do to India's marginalized people. Dr. Udit Raj was born to Dalit parents and brought up in a small village called Ram Nagar, 15 km away from Allahabad in North India. His schooling began in a primary school near his village and he did his graduation from Allahabad University. He used to ride bicycle from his village to the nearby Railway Station to catch train to Allahabad city and then walked up to his college. He was good in his studies and at the same time involved in the students and labor union movement from his early schooling.

In 1980, he got admission in India's one of the finest Jawaharlal Nehru University (JNU) in Delhi. With three hundred rupees, which his father took as a loan, he did his post-graduation. While he was studying at JNU, he applied for Union Public Civil Examination. He went to Meerut to write the exam, but ended up joining the farmers protest on the that day there and came back without writing the examination. He wrote it the following year and succeeded. He was selected for the prestigious Indian Revenue Service in 1988. He met Seema Raj, who was also undergoing the probation Indian Revenue Service training at Nagpur. They both fell in love and got married on 24 March 1990. Seema Raj came from high caste family. Her parents accepted the marriage proposal and wanted to have it big, but Dr. Udit Raj objected to the spending of lot of money in the marriage, rather he proposed to use the money for social causes. Dr. Udit Raj and his wife Seema, after their marriage worked in Income Tax in Uttar Pradesh and later in Delhi.

Dr. Udit Raj came across many caste prejudices in his life, beginning from his early schooling. He was unlike the other Dalit children, who suffer the caste prejudice silently. He and his brothers confronted any caste prejudice faced in the school and in the society. During his college, he joined the struggle faced by the farmers and labor unions and involved in the student wing. Later, after moving to Jawaharlal Nehru University,

he joined Students' Federation of India. His struggle did not end even after entering the prestigious profession in the Indian Revenue Service. The government of that time began formulating anti reservation policies in the order from Department of Personal and Training (DOPT) in 1997 and barring the reservation in promotion. The DOPT's anti reservation order sparked the fire among the SC/ST Employees and unions began mobilizing a national platform where the anti-reservation could be confronted. The SC/ST Employees, when they began meeting, urged Dr. Udit Raj to lead the mass movement. Under his leadership, All India Confederation of SC/ST Organizations was founded in 1997. Thereafter the campaign to protect reservation began and is continuing until today. Under the banner of the Confederation, the first rally was held on 26 November 1997, second on 16 November 1998, third on 13 December 1999 and the fourth on 11 December 2000 in Delhi. Due to these rallies, an environment of revolution gripped the country, and the Government bowed down before the movement. Indian Parliament had to bring Bill to ensure the reservation for SC/ST and other backward classes. Dr. Udit Raj carried the leadership of national mass movement and the challenges of the reservation become more serious after the privatization. The public and private sector of the employment has seen vast changes since independence. When India got independent, there was about 15% private sector and 85% public sectors. Now, after 60 years of independence, India has about 85% of private sectors and 15% of private sectors. There is no reservation in private sectors, which brought down the economic condition and employment for SC/ST communities. Dr. Udit Raj resigned from the government job in 2003 and continued to carry the mass.

He always believes in the people's mass movement and their participation in the parliament system. He attempted to mobilize politically by forming the India Justice Party but not succeeded. He believes nothing will work without going to the parliament; therefore, he contested Parliamentary election in 2014 from North West Delhi Constituency on the BJP ticket. Since then he has raised the issues and challenges, including the introduction of private member's bill of Reservation in Private Sectors. Dr. Udit Raj is on move every day from one corner to another, strengthening and expanding the branches of All India Confederation of SC/ST Organizations in different states. The masses are following his leadership in different parts of India.

Dr. Udit Raj believes in the power of people movement that can bring pressure on the government. Nationwide Protest on 2 April 2018 against the Supreme Court order on SC/ST Prevention of Atrocities Act is the recent event that he often refers and through which the central government had to amend the bill to ensure the SC/ST Prevention of Atrocities act is intact. He looks forward to the Mega Rally scheduled on 3 December 2018 in New Delhi. In the documentary, the politicians across the political parties and oversea dignitaries and friends said highly of Dr. Udit Raj. Former Prime Minister, Dr. Manmohan Singh says, "He is a man with a mission to uplift the marginalized people." Former Bharatiya Janta Party President – Shri Nitin Gadkari and now Union Minister says, "The politics of socio-economic empowerment is his aspiration." Former Delhi Chief Minister, Smt. Sheila Dixit says, "He helped me to understand the political concerns for Dalits." Former Chief of Indian Army and now Union Minister Mr. VK Singh says, "He is a political leader who is a friend across the political differences." Lastly, not the least is the family he has. Seema Raj, his wife having come from the higher caste stood firm along with Dr. Udit Raj for the social cause. In spite of her heavy responsibility in Indian Revenue Service, she shared the platform along with her husband on many occasion and supported him in his struggle for Dalits.

Seema Raj understood the social and political aspiration of Dr. Udit Raj even before their marriage. She supports his social concern for women empowerment and gender equality. She stood along with him when he wanted to give up his prestigious government job in 2003 to move into politics and lead the masses under the banner of All India Confederation of SC/ST Organizations. I have sat through days in his office and saw the help he extends to the poor and the rich, small and big. He writes to the government hospital for poor patients who come to seek help. He writes to the concerned department, seeking his help for job transfer or injustice done to the employees. The greatest help, the North East communities living is Delhi wanted the support he gave when we founded North East Helpline in Delhi. Our girls were targeted for sexually harassment and our men racially. In 2007, he inaugurated North East Helpline at Press Club of India, which extended help to North East communities. Truly, Dr. Udit Raj is a man from the bottom of the society, who became a crusader, particularly to save the reservation, which Dr. B R Ambedkar gave through Indian Constitution. Truly, he is a crusader for the masses, help for the needy, a good husband, and a good father at home.

- Madhu Chandra
National Secretary,
All India Confederation
of SC/ST Organizations,
Hyderabad

Beaware of Bad News

We all know that the Supreme Court diluted the Schedule Caste & Schedule Tribes Prevention of Atrocities act 1989 on 20th March 2018. A massive protest on 2nd April by Dalits made a huge impact. The Parliament amended the constitution to restore the Act and after that it was considered that it would put to an end to it. Unfortunately, a PIL has been filed in the Supreme Court and admitted also it seems that the intention of the Supreme Court is bad and malafide. This is my fervent appeal that regardless of organizations and party affiliations, please unite on this issue and participate in large number on 3rd December at Ramleela Maidan, New Delhi around 11am to press for reservation for SC/ST, OBC and Minority in Higher Judiciary.

- Dr. Udit Raj, National Chairman

Major Achievements

1. Saved reservation by introducing 3 constitutional amendments
2. Achieved reservation in Lokpaal,
3. Lakhs of people adopted Buddhism on 4th November, 2001
4. Reservations in promotion has been restored,
5. Raised highest number of Dalit issues in the parliament,
6. Support for reservation to backwards in higher education,
7. In the Bharat Bandh on April 2,2018 many innocent people were booked in false lawsuit, for which the Confederation communicated with the District Magistrate and Superintendent of the District to release thousands of people from jail,
8. Big contribution in the release of Chandrashekhar, Bhim Army Chief

Major Issues

1. Protection of reservation for Dalits, Backwards and Minorities,
2. Implementation of reservation in Judiciary and Private Sector,
3. Formation of Law for Reservation,
4. End of contract system in cleaning works,
5. Special recruitment drive to fill the backlog and empty positions,
6. Equal education policy should be implemented in the country and land be given to the landless,
7. Make Scheduled Castes and Scheduled Tribes Planning Policies,
8. Caste certificate of one state should be valid in other states as well,
9. Increment in Scholarship should be at par with the Inflation rate,
10. Constitution of National Judicial Appointment Commission with reservation,
11. Women Empowerment,
12. Issue of proper license and allotment of proper space to the Rehari and Patri vendors.

Dear Friends,

All India Confederation of SC/ST Organization is concerned about protecting the rights of underprivileged rather than promoting the interest of an individual . Since 1997, we have been demanding reservation whereas many other organizations have been focusing on caste related issues for their selfish agenda. Many such organizations are engaged in table talks and indoor discussion and on the contrary All India Confederation has been spearheading the struggle for preventing the erosion of reservation in Government jobs and educational institutions. People have misjudged us, but history will absolve us of any false allegations. What can be more ironical than the fact that when consciousness in Bahujan society rose the safeguards for SC/ST community were diluted. Our people are emotionally obsessed to leadership of an individual, but they didn't have the realisation that it would come at the cost of irreversible erosion in government jobs and education. Thousands of engineering colleges, medical colleges and universities opened up in the private sector but lacked inclusiveness and were unaffordable.

In 1993, the Supreme Court by it's own judgement usurped the power to appoint the judges, and leaders of Bahujan Samaj witnessed from the sidelines and failed to rise to the occasion. Had they opposed the extra constitutional act of Supreme Court then we would not have witnessed the judicial overreach wherein rights given by Parliament are being diluted by the courts. The people's representatives were selfish and will remain so and common people keep supporting leaders of their caste without any gain. On 3rd December, 2018 if lakhs of people don't assemble at Ramlila Ground, New Delhi to gheraav Supreme Court, remember that laws made in favour of SC/ST/OBC would keep getting blocked by the judicial activism. In other societies people oppose unjust judgement of courts and in USA, blacks fought tooth and nail against white judges and as a result that stopped partial judgement. So long as reservation is not secured in higher judiciary, there is no hope for justice for SC/ST and OBCs. Judges are judging the merits of all others, whereas they are appointed without the basis of merit. The chief justice of high court recommends any lawyer to become judge, does he appear in exam or interview is conducted or are his prior cases scrutinised? The whole higher judiciary has become mockery and appointments are done on the consideration of nepotism, castes or payback to those who oblige to make judges. Thus it is clear that, the judges are not appointed on basis of marriage, then how can they determine other's merit? Only way to correct this appointment procedure is to recruit them either through All India Judicial Services or through National Judicial Appointment Commission, which was thwarted by the same judiciary.

There is a misnomer that political power is sufficient to effect change. In the caste hierarchy the SCs/STs are at the bottom and the other three strata of the caste will not support SC/ST based leaders or parties in getting elected. The ideology and programs are secondary and what is primary is caste superiority and strong bias against the lower castes. Coming to the next higher strata, that is the OBCs, the mindset persists to be Brahminical and majority continue to feel superior. Dalit, OBC and Minorities form 85% of population but lack of consciousness and awareness is keeping them divided. Only the so called upper caste enjoy easy and natural support in getting elected and are therefore successful and powerful. The fight to capture political power should go on but on the other hand struggle should be strengthened to protect the rights. On 2nd April, 2018, if Dalits would have not succeeded in Bharat Bandh then it would not have been possible to restore the SC/ST Act and withdraw the 5th March, 2018 circular of UGC which diluted reservation in Universities. Dalits and Tribals should forget that their representatives' like MPs and MLAs will fight for them. The reason is that political parties get them elected and hence they are bound to obey the leadership. Bahujans should introspect that when it comes to electing their representative, they vote for parties even if Chamcha/ corrupt or uneducated are fielded and those who are sincere and have struggled are ignored. Mind it, those who are fighting on streets are the ones getting their demands fulfilled, for example, Jaats in Haryana, Patels in Gujarat and Farmers in Mumbai.

Has any leader other than Dr. Udit Raj, National President, All India Confederation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Organizations, raised as many Dalit issues in the Parliament? He presented the private member bill for reservation in private sector. He not only supported the Bharat Bandh movement of 2nd April, 2018 but did spare his own party when needed. He aggressively appealed in Parliament for the release of Mr. Chandrashekhar, the Chief of Bhim Army. People should turn up in large numbers on 3rd December 2018 at ramlila maidan in a solid show of strength , the same way as they did on April 2, 2018. Now there is no other way. This is not a personal struggle of Dr. Udit Raj or the Confederation, but of the entire Dalits, Tribals, Backwards and Minorities.

By: Devi Singh Rana, Om Prakash Singhamar, Parmendra, Girish Chandra Pathre, Satya Narayan, Savita Kadian Panwar, Sanjay Raj, Rajan Hisam, Aditya Kumar Navin (Delhi), Sushil Kamal, Neeraj Chak, Raj Kumar (UP) , Siddharth Bhojne, Deepak Tabhane, Sanjay Kamble, (Maharashtra), S.P. Jaravata, Vishwanath, Satwan Bhatia, Mahasinh Bhurania (Haryana), Tarasam Singh Gharu (Punjab), Maniram Badgujar, Vishram Meena, Mukesh Meena (Rajasthan), Babu Singh, Vijay Raj Ahirwar (Uttarakhand), Article Malik, DK Behera (Orissa), Paramahansa Prasad, Narendra Chaudhary, Vipin Toppo (M.P.), Ramubhai Vaghela, Utpal Kulkarni (Gujarat), S. Karpaiya, P. N. Perumal (Tamil Nadu), Raman Bala Krishnan (Kerala), Madhu Chandra (Manipur), K. Maheshwar Raj, Prakash Rathore (Telangana), Palitati Panta Rao (Andhra Pradesh), Harsh Meshram, Pradeep Sukhdev (Ch.), P. Baala, Sadan Nasar, Subrata Batul (W. Bengal), Madhusudan Kumar, Wilfrid Karketta (Jharkhand), R K Kalsotra, B.L. Bharadwaj (J&K), Madan Ram, Shivdar Paswan, Shiv Pujan (Bihar), J. Srinivasulu, R. Raja Segaran, Thipes, P. Shankar Das (Karnataka), Sitaram Bansal, (H.P.), Pradeep Baspor, Jai Karan (Assam), C.B. Subba (Sikkim), Prakash Chandra Biswas (Tripura)

VOICE OF BUDDHA

Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

● Year : 21 ● Issue 23 ● Fortnightly ● Bi-lingual ● Total Pages 8 ● 1 to 15 November, 2018

March Delhi ! March Delhi !! March Delhi !!!

ALL INDIA CONFEDERATION OF SC/ST ORGANIZATIONS

Calls

Saving Reservation for SC/ST/OBCs, Reservation in Judiciary & Private Sector and To Stop Atrocities

Dr. Udit Raj (Ex. IRS),
National Chairman

RALLY

03rd December, 2018

Monday, at 10 AM

Ramlila Ground, New Delhi

Join in large number to make the Rally successful

By: Devi Singh Rana, Om Prakash Singhmar, Parmendra, Girish Chandra Pathre, Satya Narayan, Savita Kadiyan Panwar, Sanjay Raj, Rajen Hijam, Samuel Massey, Aditya Kumar Naveen (Delhi), Sushil Kamal, Neeraj Chak, Raj Kumar (UP), Siddharth Bhojane, Deepak Tabhane, Sanjay Kamble (Maharashtra), S.P. Jarawata, Vishwanath, Satyawan Bhatia, Mahasingh Bhurania, (Haryana), Tarshem Singh Gharu, Rohit Sonkar (Punjab), Maniram Badgurjar, Pancham Ram, Vishram Meena, M. L. Rasu, Mukesh Meena (Rajasthan), Babu Singh, Vijay Raj Ahirwar (Uttarakhand), Alekh Malik, D.K Behera (Orissa), Paramhans Prasad, Vipin Toppo, Narendra Chaudhary (M.P.), Ramubhai Vaghela, Utpal Kulkarni (Gujarat), S. Karuppaiah, P. N. Perumal (Tamil Nadu), Raman Bala Krishnan (Kerala), Madhu Chandra (Manipur), K. Maheshwar Raj, Prakash Rathore (Telangana), Palteti Penta Rao (Andhra Pradesh), Harsh Meshram, Pradeep Sukhdeve (Ch.), P. Bala, Sadan Naskar, Subrata Batul (West Bengal) Madhusudan Kumar, Welfrid Kerketta (Jharkhand), R.K. Kalsotra, B.L. Bhardwaj (J&K), Madan Ram, Sheodhar Paswan, Shiv Pujan (Bihar), J. Srinivasulu, R. Raja Segaran, Thippesh, P.Sankara Doss (Karnataka), Sitaram Bansal (H.P.), Pradeep Basfore, Jai Karan (Assam) , C.B. Subba (Sikkim) , Prakash Chandra Biswas (Tripura)

Corres.: T-22 Atul Grove Road, Connaught Place. New Delhi -110001 Ph.No. 011-23354841/42, Mob.: 9868978306, Fax : 011-23354843

Publisher, Printer and Editor - Dr. UDIT RAJ (FORMERLY KNOWN AS RAM RAJ), on behalf of Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42, Telefax:23354843, Printed at Sanjay Printing Works, WZ-4A, Basai Road, New Delhi.
Website : www.aiparisangh.com, www.uditraj.com E-mail: parisangh1997@gmail.com Computer typesetting by Ganesh Yerekar